

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्रम संख्या	अपील संख्या	अपीलार्थी का नाम	बनाम
1.	714 / 2017	बंशीलाल	डिप्टी डायरेक्टर (माध्यमिक), शिक्षा, अजमेर डिवीजन, अजमेर, राजस्थान एवं अन्य।
2.	1205 / 2017	कजोड़ीमल	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, ज्योतिनगर, जयपुर एवं अन्य।

आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित -

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

- उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 714 / 2017 बंशीलाल बनाम डिप्टी डायरेक्टर, (माध्यमिक), शिक्षा, के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
- इस अपील में अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :- "It is therefore most humbly prayed that this appeal may kindly be allowed and call for the record relating to the case and after examining the same the impugned orders dated 01-02-2016 (Annex-7) and order dated 29.11.2016 (Annex-8) may kindly be quashed and set aside and further be directed to the respondents to count his services from the date of initial appointment 1.e. 3.7.1985 for the purpose of third selection grade/ACP and arrears be also granted with interest of 9% P.A.
Any other order, which this Hon'ble Court deem just and proper may kindly be passed in favour of the appellant."
- अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति के पश्चात कार्यालय पंचायत समिति, कुचामन सिटी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.1985 द्वारा की गई थी। जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 03.07.1985 को कार्यग्रहण किया। बाद में अपीलार्थी का चयन जिला कर्मचारी वर्ग समिति (जिला परिषद) नागौर द्वारा उनक पत्रांक 120 दिनांक 11.05.1988 एवं 1333 दिनांक 04.06.1988 द्वारा दिये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमित की गई।
- अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को 9 वर्षीय एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 03.07.1985 से गिनते हुए दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 01.02.2016 के द्वारा अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ दिये जाने में प्रथम नियुक्ति की तिथि

07.09.1988, जो कि अपीलार्थी की स्क्रीनिंग किये जाने की तिथि से गिनती की गई, जो गलत है।

5. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि एसीपी नियमित नियुक्ति की तिथि से देय है। ad-hoc के रूप में दी गई सेवाओं को एसीपी के लिए नहीं गिना जा सकता है।
6. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति की तिथि 03.07.1985 होना बताया है। जबकि अपीलार्थी ने नियुक्ति आदेश दिनांक 01.07.1985 की पालना में कार्यग्रहण किया। नियुक्ति आदेश दिनांक 01.07.1985 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को जो नियुक्ति दी गई थी, वह अस्थायी तौर पर सत्रांत तक दी गई थी। उक्त नियुक्ति आदेश से यह भी स्पष्ट है कि नियुक्ति अस्थायी तौर पर 6 माह के लिए अथवा चयनित अध्यापक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए दी गई थी। अतः आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी पर उक्त नियुक्ति नियमित नहीं थी तथा ad-hoc के रूप में की गई थी। अतः आदेश दिनांक 01.07.1985 के द्वारा नियुक्ति को नियमित नियुक्ति नहीं माना जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14491/2013 में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बनाम श्रीमती इंदु शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

"7. In view of the admitted factual matrix, the controversy raised herein may not detain this Court for long in the face of authoritative pronouncement on the issue by the Hon'ble Apex Court of the land in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), wherein the Hon'ble Supreme Court held that promotion has to be in the existing cadre in service. Adhoc appointment is always to a post, but not to the cadre/service and is not made in terms of recruitment rules for regular appointment. In case of ad hoc employees, stagnation is till regularization is made. The stress in the present case is on 'regular' appointment to cadre/service. The question of promotion arises only when appointment is a regular appointment. Further, appointment to the post is not relevant; on the other hand, what is relevant is the period relatable to cadre of the service. Therefore, while reckoning the required length of service, the period of ad hoc service has to be excluded.

In view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), it is evident that the respondent-employee was not appointed in any existing

cadre/service, and therefore, ad hoc/temporary appointment will not qualify to be treated as 'regular appointment'.

9. For the reasons and discussions herein above and in view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), the impugned order passed by the learned Tribunal cannot be sustained and has to be quashed and set aside.

10. Ordered accordingly.

11. Consequently, the writ application succeeds. The impugned order dated 11th December, 2002, is hereby quashed and set aside.

12. In view of the final adjudication on the writ application, the stay application stands closed.

13. However, in the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी (2009) 12 एस.सी.सी. 49 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2009 में स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं कि चयनित वेतनमान हेतु नियमित नियुक्ति की तिथि से ही सेवा की गणना की जानी है जिसकी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में पुनः पुष्टि की है।
8. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent -

employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

9. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि जो सेवाएं अपीलार्थी ने दिनांक 03.07.1985 से नियमितकरण का आदेश पारित किये जाने तक दी है, उसे नियमित नियुक्ति नहीं माना जा सकता है। इसलिए उस समय की सेवाएं ad-hoc के रूप में की गई थी और वो सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान और अन्य लाभ के लिए नहीं जुड़वा सकता है।
10. अतः उपरोक्त दोनों अपीलों में कोई बल नहीं होने से अपीलें खारिज की जाती है।
11. मूल आदेश अपील संख्या 714/2017 में एवं इसकी छायाप्रति अपील संख्या 1205/2017 में सलंगन की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)